Publication Date 01.08.2025
Postal Registration No. G/CHD/0096/2024-26
Registrar of Newspapers of India
Regd. No. 46809/70 I Total Pages 32
Posted at MBU Chandigarh 1st of Every Month

हरियाणा सहकारी प्रकाश

Haryana Sahkari Parkash

HARCOFED

International Year of Cooperatives 2025
Cooperatives Build a Better World

वर्ष : 56 | अंक 08 | 1 अगस्त, 2025 | वार्षिक मूल्य : 500/- | प्रति कापी : 50/-

79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

HARCOFED
Bays No. 49-52, Sector - 2, Panchkula
https://www.harcofed.org.in
harcofed@ymail.com

दिनांक 5 जुलाई 2025 को इंद्रधनुष सभागार, सैक्टर–5, पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस– 2025 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सहकारिता मंत्री हरियाणा, डॉ. अरविंद कुमार शर्मा जी का स्वागत करते सहकारिता विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री विजयेन्द्र कुमार, भा.प्र.से।

दिनांक 5 जुलाई 2025 को इंद्रधनुष सभागार, सैक्टर–5, पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस– 2025 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सहकारिता मंत्री हरियाणा, डॉ. अरविंद कुमार शर्मा जी का स्वागत करते रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा श्री राजेश जोगपाल भा.प्र.से व संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां एवं प्रबंध निदेशक हरकोफैड श्री नरेश गोयल।

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा

सहकार से समृद्धि
श्री नायब सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा
के कुशल नेतृत्व में
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025
राज्य स्तरीय समारोह
डॉ अरविंद कुमार शर्मा

2025
International Year
of Cooperatives
Cooperatives Build a Better World

श्री नायब सिंह सैनी, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा
के कुशल नेतृत्व में
Cooperative Bank
Platinum
6522 9200 0000 0000
06/32
CARDHOLDER NAME

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025

हरियाणा सहकारी प्रकाश

मुख्य संरक्षक
विजयेंद्र कुमार, भा.प्र.से.
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
सहकारिता विभाग, हरियाणा

संरक्षक
राजेश जोगपाल, भा.प्र.से.
रजिस्ट्रार सहकारी समितियां,
हरियाणा

मुख्य सम्पादक
नरेश गोयल
प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड

सम्पादक
सौरव शर्मा

सुविचार

किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो मान लीजिए आप गलत मार्ग पर हैं।

-स्वामी विवेकानन्द

'हरियाणा सहकारी प्रकाश' में प्रकाशित लेखकों के विचारों के साथ हरकोफैड का सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह लेखकों के अपने विचार हैं।

हरियाणा सहकारी प्रकाश की विज्ञापन दरें :–

क्र.सं.	विवरण प्रति प्रकाशन	रुपये
1.	पूरा पृष्ठ टाईटल रंगीन	30000/-
2.	पूरा पृष्ठ रंगीन	20000/-
3.	पूरा पृष्ठ श्याम–श्वेत	12000/-
4.	आधा पृष्ठ श्याम–श्वेत	6000/-

इस अंक में पढ़िए

सम्पादकीय 6

प्रोफेसर अशीम कुमार घोष बने हरियाणा के 19वें राज्यपाल 7

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का हुआ अनावरण 8–9

भारत मण्डपम, दिल्ली में मंथन बैठक का हुआ आयोजन 10–11

पंचकुला में मनाया गया राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस – 2025 12–13

हरको बैंक का प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी हुआ लॉन्च 14

चंडीगढ़ में नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस का हुआ आयोजन 15–16

करनाल सहकारी चीनी मिल ने राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकि दक्षता में प्राप्त किया प्रथम पुरस्कार 17–18

दि हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि. चण्डीगढ़ 18

रोहतक वीटा प्लांट के दायरे में 158 नए बूथ स्थान चिन्हित : डॉ. अरविंद शर्मा 19

शोक समाचार 19

वॉकथॉन का आयोजन 20

अमूल का खतराज प्लांटः एकीकृत डेयरी वैल्यू चेन का चमकता उदाहरण 21–22

हरकोफैड की सामान्य निकाय वार्षिक बैठक हेतु प्रतिनिधियों के नामांकन बारे 23–24

हरकोफैड की सदस्यता लेने बारे आवेदन पत्र 25

लघुकथाः धागा 26

पौधे की व्यथा 27

डेयरी क्षेत्र का विकास : श्वेत क्रांति 2.0 28–29

हरकोफैड द्वारा पूरे हरियाणा में किया गया एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण कार्यक्रम लगाए 1100 पौधे 30

विज्ञापन 31

E-MAIL
harcofed@ymail.com
harcopress@gmail.com
Website
https://www.harcofed.org.in

सम्पादकीय

79वां स्वतंत्रता दिवस

2025 में स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस होगा। 15 अगस्त, भारत के स्वतंत्रता संग्राम और देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने और उनकी कुरबानी को सलाम करने का दिन है क्योंकि इस आज़ादी को पाने के लिए भारत ने 200 साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा अपार बलिदान, साहस और एकता से भरी हुई है। 1857 के विद्रोह से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारी स्वतत्रता के लिए कई चुनौतियों का सामना किया।

इस ऐतिहासिक दिन पर हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री, दिल्ली में लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन आम भाषण नहीं होता, बल्कि राष्ट्रीय गौरव के अवसर पर यह राष्ट्र के सामने उसके नेता का उद्‌बोधन होता है। यह दिन पूरे देश को एक साथ लाता है, सभी भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता पर गर्व करने का अवसर देता है और हमें अपने देश के लिए कुछ करने और इसे और अधिक महान बनाने की प्रेरणा देता है।

स्वतंत्रता दिवस का अर्थ केवल झंडा फहराना और भाषण देना नहीं है। इसका अर्थ है अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए काम करना, समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, अपने संविधान का पालन करना और अपने देश के कानूनों का सम्मान करना। स्वतंत्रता के 78 वर्षों में हमारे देश ने बहुत प्रगति और विकास किया है जिससे वैश्विक स्तर पर आज भारत की एक विशेष पहचान बनी है।

स्वतंत्रता दिवस हमें एक साथ आने, अपने मतभेदों को दूर करने और अपने राष्ट्र के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करता है। आइऐ, हम सब मिलकर अपने देश को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लें और सहकारिता से जुड़कर देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का संकल्प लें।

जिसका ताज हिमालय है
जहां बहती गंगा धारा है
सत्यमेव जयते जहां नारा है
वह भारत देश हमारा है

भारत माता की जय

प्रोफेसर अशीम कुमार घोष बने हरियाणा के 19वें राज्यपाल

21 जुलाई 2025 को प्रोफेसर अशीम कुमार घोष ने हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रख्यात शिक्षाविद् प्रो. अशीम कुमार घोष को हरियाणा राजभवन, चंडीगढ़ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री शील नागू ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। उन्होने श्री बंडारू दत्तात्रेय, पूर्व राज्यपाल हरियाणा का स्थान लिया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली समेत हरयिाणा के सभी मंत्री एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

हरियाणा के राज्यपालों में प्रो. घोष पश्चिम बंगाल से सबंध रखने वाले तीसरे राज्यपाल हैं। इनसे पहले हरियाणा के दूसरे राज्यपाल रहे श्री बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जिनके पास अब तक के हरियाणा के राज्यपाल का सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है (15 सितंबर 1967–26 मार्च 1976) एवं चौथे राज्यपाल श्री हरि आनन्द बरारी जी भी पश्चिम बंगाल से थे।

प्रोफेसर अशीम कुमार घोष जी का जन्म सन् 1944 में हावड़ा, ब्रिटिश भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विवेकानंद संस्थान, हावड़ा से पूरी की। तत्पश्चात् विद्यासागर कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वे 1966 से कोलकाता के मंनिद्र चंद कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। आप सन् 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का हुआ अनावरण

हर तहसील में पांच-पांच मॉडल सहकारी गांव विकसित होंगे

सहकारी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुरुवार 24 जुलाई 2025 को दिल्ली के अटल अक्षय ऊर्जा भवन ऑडिटोरियम में नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि यह नीति 2025 से 2045 तक अगले दो दशकों के लिए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा, देश के अर्थतंत्र के विकास करने की क्षमता केवल सहकारिता क्षेत्र में है। सहकारिता नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि नीति का केंद्र आम व्यक्ति, दलित और आदिवासी हैं। एक वाक्य में कहा जाएं तो इसका विजन सहकार से समृद्धि के माध्यम से 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।

हर पंचायत में एक समिति का लक्ष्यः उन्होने कहा, सहकारिता की पहुंच जमीनी स्तर पर तक सुनिश्चित करने के लिए नई नीति में प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक सहकारी समिति बनाने का लक्ष्य है। नई नीति में देश की 8 लाख 42 हजार से अधिक सहकारी संस्थाओं को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा, नई नीति के बाद हर तहसील में पांच गांवों को मॉडल सहकारिता गांव बनाया जाएगा।

हर सदस्य आत्मनिर्भरः शाह ने कहा, बीते चार साल में देश में सहकारिता ने कई सिद्धियां यां हासिल हासिल की कीं पर जो सबसे बड़ी सिद्धी है वो यह है कि आज सहकारिता से जुड़ा हर सदस्य आत्मनिर्भर बन गया है। उन्होंने बताया, नई नीति लाने का उद्देश्य

सहकारी संस्थाओं को आधुनिक बनाना है, ताकि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहयोग मिल सके।

नई सहकरिता नीति की मदद से किसानों को मंडियों–बिचौलियों पर निर्भर रहने से मुक्ति मिलेगी। गांवों में रोजगार के नए मौके बनेंगे। इसकी खासियत है कि इसका जोर युवाओं–महिलाओं की सहकारी समितियों में भागीदारी बढ़ाने पर है।

बता दें कि, सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में 48 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसने नई सहकारिता नीति का मसौदा तैयार किया। समिति ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना एवं गुरुग्राम में कई कार्यशालाएं आयोजित कर छह सौ से ज्यादा सुझावों पर विचार किया और नीति में उन्हें समाहित किया। इसमें सभी स्तरों की सहकारी समितियों, शिक्षाविदों, राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की भागीदारी रही।

सहकारी क्षेत्र का जीडीपी में योगदान तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य : मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2027 तक हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेंगे। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2034 तक सहकारी क्षेत्र का देश की जीडीपी में योगदान तीन गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, मुरलीधर मोहोल, सहकारिता सचिव, डॉ. आशीष कुमार भूटानी और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश प्रभु सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

भारत मण्डपम, दिल्ली में 'मंथन बैठक' का हुआ आयोजन

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अगुवाई में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों ने लिया बैठक में भाग

दिनांक 30 जून 2025 को भारत मण्डपम, दिल्ली में माननीय केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्रियों के साथ सहकारिता क्षेत्र की प्रगति और विकास पर मंथन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा कहा गया कि भारत सरकार राज्यों को साथ लेकर निरंतर सहकारी क्षेत्र को उन्नति और समृद्धि की ओर ले जा रही है। साथ ही केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति की घोषणा करने वाली है। हर राज्य राष्ट्रीय नीति के तहत स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द सहकारिता नीति बनाए। साथ ही, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय से जुड़कर सहकारी प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दे।

हरियाणा के सहकारिता मंत्री ने मंथन बैठक में लिया भाग :– सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने दिल्ली के भारत मण्डपम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में राज्यों के सहकारिता मंत्री, प्रशासनिक सचिवों के साथ हुए मंथन बैठक में शिरकत की। बैठक में सहकारिता आंदोलन को गति देने, हर घर को सहकार से जोड़ने समेत विभिन्न लक्ष्यों

पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद हरियाणा की सहकार में भूमिका पर सहकारिता मंत्री ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि देश की आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सहकारिता आंदोलन को पुर्नजीवित करने का जो संकल्प लिया गया है, उसे केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह के कुशल मार्गदर्शन में पूरी शिद्दत और गंभीरता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 11 साल में हरियाणा ने केंद्र की सभी योजनाओं में बढ़–चढ़कर भागीदारी करते हुए अपना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सहकार आंदोलन को पुर्नजीवित करने में हरियाणा अहम भूमिका अदा करेगा।

त्रिभुवन पटेल सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने की हो रही क्रांतिकारी पहल

डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने अपनी चार साल की यात्रा में देश के गरीब, किसान, युवा और महिला वर्ग को जिस बदलाव को महसूस करवाया है, वह देश की पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने के लिए तैयार हो रहा है। देश की कृषि क्षेत्र व सहकारिता क्षेत्र की बिखरी ताकत को समेटने के लिए प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी पहल त्रिभुवन पटेल सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने की हो रही है, वो भारत निर्माण में आधारशिला साबित होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा डिजीटल बैंकिंग, ऑनलाइन खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा दे रहा है।

वीटा के 350 नए बूथ स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर कराए जाएंगे उपलब्ध

हरियाणा में सहकारी समितियों, दुग्ध संघों, सहकारी बैंकों और फेडरेशनों ने जिस प्रकार किसानों को सशक्त, आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने में भूमिका निभाई है, वह पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। सहकारी ऋण योजनाओं को सरल और सुलभ बनाकर, एफ.पी.ओ को प्रोत्साहन देकर और हैफेड़ के माध्यम से किसानों को बाज़ार से जोड़कर हम किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सार्थक प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने इस साल के बजट में सहकारिता विभाग के लिए लगभग 59 प्रतिशत की अभूतपूर्व बढ़ोतरी करते हुए 1254.97 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए डेयरीफैड के माध्यम से प्रदेश में 15 प्रतिशत अधिक दूध संकलन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में दूध संकलन केंद्रों की स्थापना और जिलास्तर पर चिलिंग प्लांट्स लगाने से वीटा के उत्पादों को अधिक विस्तार और बाजार मिलेगा। साथ ही वीटा के 350 नए बूथ स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

पंचकुला में मनाया गया राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस – 2025

नई सहकारिता नीति लाएगी समाज, देश में बदलाव

सीएम पैक्स से खुलेंगे जनऔषधि केंद्र, सीएससी सेंटर व गैस स्टेशन

दिनांक 5 जुलाई 2025 को पंचकूला के इन्द्रधनुष सभागार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस–2025 का भव्य कार्यक्रम सहकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा आयोजित किया गया।

इस अवसर पर माननीय सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद कुमार शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्ज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए सहकार बंधुओं को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस–2025 शुभकामनांए दी और कार्यक्रम को भव्य रूप के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने हरियाणा में गन्ना उत्पादकों को हार्वेस्टिंग के दौरान आने वाली परेशानियों के समाधान के लिए हरको बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाने की घोषणा की जिससे युवाओं, किसानों को हार्वेस्टिंग मशीनों के व्यवसायिक इस्तेमाल से आर्थिक तौर पर मजबूत होने के अवसर मिलेंगे। सहकारिता मंत्री ने कहा कि एक समय में सहकारिता संस्थाओं के माध्यम से महज खाद, दवाई, लोन संबंधी काम ही होते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज सहकारी समितियों के माध्यम से जन औषधी केंद्र, सी.एस.सी सेंटर, गैस स्टेशन जैसे 25 प्रकार के काम करने के अवसर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह की बजट घोषणा के तहत 500 सी.एम. पैक्स का गठन करने की दिशा में प्रदेश में अब तक 141 सी.एम. पैक्सों का गठन हो चुका है। उन्होंने कहा कि पैक्सों के माध्यम से छोटे वेयर हाउस भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे पी.डी.एस प्रणाली के तहत खाद्य की आपूर्ति इनके जरिए सम्भव हो सके। देश में 140 करोड़ भारतीय को सहकार से जोड़ने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार निरन्तर कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सहकार से जुड़े प्रत्येक नागरिक के जीवन मे आने वाले समय मे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सहकारिता विभाग हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेन्द्र कुमार, भा.प्र.से ने कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा, विशिष्ट अतिथिगणों, सहकारिता क्षेत्र के वरिष्ठ पदाधिकारीगणों, हरियाणा की सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों, हरियाणा के कोने–कोने से पधारे हुए सहकार बंधुओं, अतिथियों व पत्रकार–छायाकार बंधुओं का स्वागत किया। उन्होने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और आत्मचिंतन का अवसर लेकर आया है। सहकारिता कोई नई अवधारणा नहीं है, यह हमारे ग्रामीण समाज की आत्मा रही है, हमारे सामूहिक स्वभाव की पहचान रही है। जब भी समाज में विषमता, असमानता और शोषण की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तब सहकारिता की भावना ही वह माध्यम बनती है जो सबको जोड़ती है, सबको समान अवसर और भागीदारी देती है। यही भावना आज भारत के ग्राम्य जीवन को सशक्त बना रही है, और यही भावना "विकसित भारत" के निर्माण की आधारशिला है। हरियाणा राज्य सहकारिता क्षेत्र में देशभर में अग्रणी रहा है। आज राज्य में 33,000 से

अधिक सहकारी समितियाँ सक्रिय हैं, जो सीधे तौर पर 54 लाख से अधिक लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही हैं। इन समितियों के माध्यम से कृषक भाइयों को ऋण, बीज, खाद, मशीनरी, विपणन सहायता, और प्रशिक्षण उपलब्ध हो रहा है।

माननीय सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने सहकारिता के भविष्य को नई दृष्टि और ऊर्जा दी है। आज जब पूरा देश 'विकसित भारत /2047' की ओर बढ़ रहा है, तब सहकारिता ही वह वाहन है जो प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को इस यात्रा में सहभागी बना सकती है। "सहकार से समृद्धि" का मंत्र अब नारा नहीं, बल्कि एक ठोस कार्ययोजना का स्वरूप ले चुका है।

उन्होने मंच से सभी से आह्वान किया कि हम सब मिलकर इस आंदोलन को ओर अधिक ऊँचाई पर ले जाएँ। हम अपने गाँवों में सहकारिता के नए प्रयोग करें – कृषि में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और पर्यावरण संरक्षण में। सहकारिता को नवाचार, तकनीक और युवाशक्ति से जोड़ें, ताकि यह आंदोलन भविष्य की चुनौतियों का भी समाधान बन सके।

हरको बैंक का प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी हुआ लॉन्च

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा हरको बैंक के प्लेटिनम डेबिट कार्ड को भी लॉन्च किया गया। पांच लाख रुपए तक के इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल देश के एयरपोर्ट लांज में भी किया जा सकेगा।

साथ ही प्रदेश के फरीदाबाद व महेंद्रगढ़ जिला के अधिकारियों को शत प्रतिशत पैक्सों को कम्प्यूटरीकरण किए जाने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं 4 पात्रों को वीटा बूथ अलॉटमेंट के पत्र जारी किए।

कार्यक्रम के अंत में रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा श्री राजेश जोगपाल भा.प्र.से ने माननीय मुख्य अतिथि सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा एवं सभी सम्मानीत अतिथिगणों का धन्यवाद किया एवं यह अश्वस्त किया कि सहकारिता विभाग हरियाणा सहकार से समृद्धि के सपने को साकार रूप देने में सक्रीय भूमिका निभाएगा।

इस अवसर पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता, पूर्व विधायक लतिका शर्मा, चेयरमैन शिवालीक बोर्ड हरियाणा श्री ओम प्रकाश देवीनगर, लैंड मोर्गेज बैंक के उपाध्यक्ष श्री राम जतन गुर्जर डमौली एवं सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

चंडीगढ़ में नाबार्ड के 44वें स्थापना दिवस का हुआ आयोजन

सहकारिता मंत्री ने प्रबुद्धजनों को किया संबोधित – बताया हरियाणा की सहकारी क्रांति का रोडमैप

हरियाणा कृषि नवाचार, फसल विविधीकरण और प्रसंस्करण आधारित खेती में बना अग्रणी राज्य

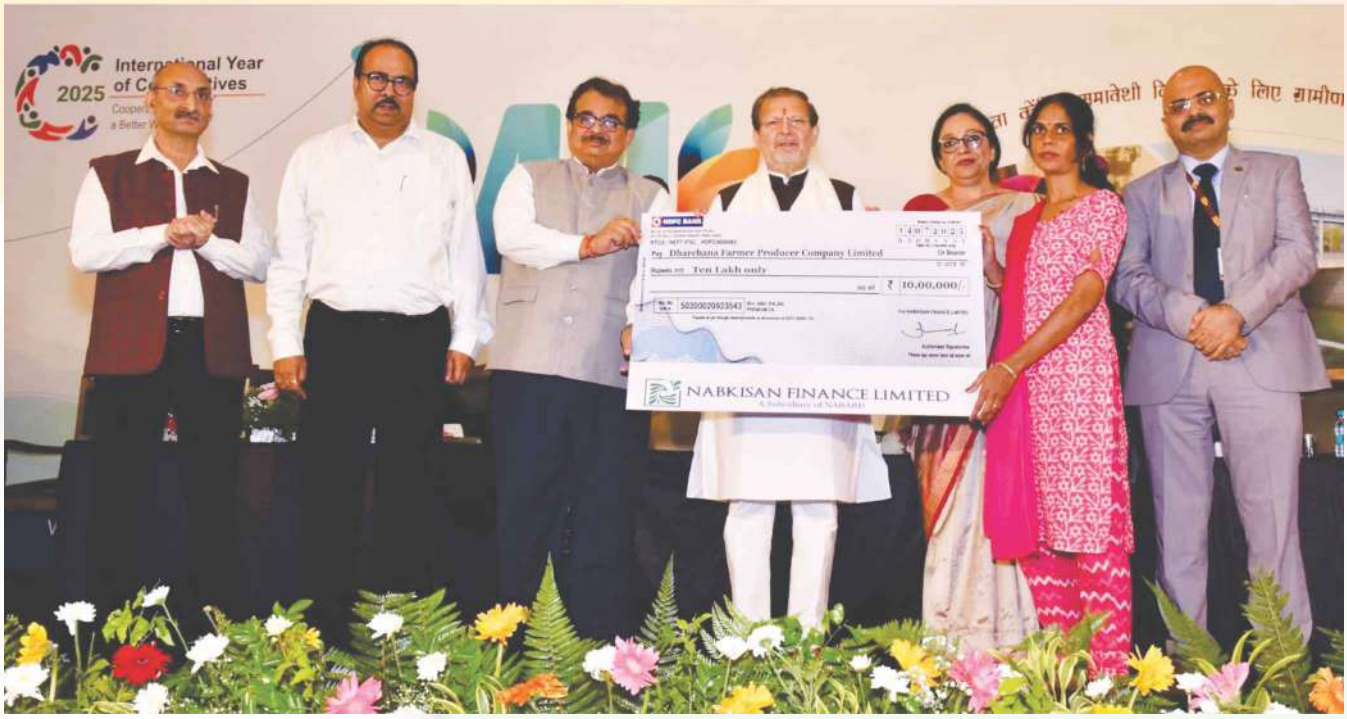

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा चण्डीगढ़ के ललित होटल में नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा चंडीगढ़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उपस्थित प्रबुद्धजनों को संबोधित किया। उन्होने कहा कि किसान की समृद्धि के बिना विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। इस दिशा में नाबार्ड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हरियाणा न केवल देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है बल्कि कृषि नवाचार, फसल विविधीकरण और प्रसंस्करण आधारित खेती में भी अग्रणी राज्य बन चुका है। ऐसे में नाबार्ड की उपस्थिति हरियाणा के समग्र ग्रामीण विकास में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा रही है। पैक्स कंप्यूटरीकरण, के. सी.सी का डिजीटलीकरण, एफ.पी.ओ, जेएलजी व एसएचजी नेटवर्क की मजबूती और सहकारी संस्थाओं को तकनीकी प्रशिक्षण व समर्थन देने जैसे अनेक आयामों में नाबार्ड का योगदान बहुआयामी और दूरगामी रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को डिजीटल, पारदर्शी और जन–केंद्रित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। इस दिशा में नाबार्ड एक प्रेरक शक्ति बनकर कार्य कर रहा है। आज सहकारी संस्थाएं केवल ऋण, खाद व बीज वितरण तक सीमित नहीं रही बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में ये संस्थाएं जन औषधि केंद्र, गैस स्टेशन, सीएससी सेंटर सहित 25 से अधिक सेवाओं का माध्यम बन चुकी हैं।

सरकार सशक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में कर रही ठोस पहल : उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में सरकार नई सहकारिता नीति के माध्यम से आत्मनिर्भर राज्य और कृषि आधारित सशक्त अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में ठोस पहल कर रही है। नाबार्ड के सहयोग से छोटे गोदामों की स्थापना, वित्तीय सहायता और तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देकर किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक की पूरी श्रृंखला में मजबूती दी जा रही है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न और विकसित भारत की कल्पना को साकार करने में सहकारिता की यह नई गति मील का पत्थर साबित हो रही है। निवेदिता तिवारी मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड हरियाणा ने बताया कि नाबार्ड ने पिछले चार दशकों में कृषि वित्त, सहकारी संस्थाओं के सशक्तीकरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण, वित्तीय समावेशन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण कौशल एवं उद्यमिता विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाबार्ड ने किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों, गैर–कृषि उत्पादक संगठनों जैसे ग्रामीण संगठनों का गठन और पोषण किया है। पिछले 43 वर्षों में अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए नाबार्ड ने सहकारी बैंकों को निरंतर पुनर्वित्त सहायता उपलब्ध करवाई है। बुनियादी ढांचे सीबीएस और सीबीएस प्लस, पैक्स कंप्यूटरीकरण और टेक्नोलोजी विकास के जरिए सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाने का निरंतर प्रयास किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव, एस.एल.बी.सी हरियाणा के संयोजक ललित तनेजा, नाबार्ड पंजाब क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक वी.के आर्या और नाबार्ड हरियाणा क्षेत्र की मुख्य महाप्रबंधक निवेदिता तिवारी सहित सरकार एवं बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, एस.एल.बी.सी. के समन्वयक, पैक्स, एफ.पी.ओ व एन.जी.ओ के प्रतिनिधि, नाबार्ड के अधिकारी एवं कर्मचारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सरकार ने 500 सीएम पैक्स के गठन का रखा लक्ष्य : सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने 500 सी.एम–पैक्स के गठन का लक्ष्य रखा है जिनमें से 161 पहले ही गठित की जा चुकी हैं। इन मल्टीपर्पज पैक्स के माध्यम से गांवों में छोटे वेयरहाउस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिससे किसानों को लाभ मिलने के साथ–साथ ग्रामीण युवाओं को रोजगार और स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हर गांव में पैक्स के संकल्प को साकार करने की दिशा में सहकारिता आंदोलन एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। सहकार से समृद्धि के मंत्र को आधार बनाकर प्राथमिक कृषि साख समितियों को मल्टीपर्पज संस्थाओं में परिवर्तित किया जा रहा है ताकि खाद, बीज, ऋण, भंडारण, विपणन जैसी सभी सुविधाएं किसानों को एक ही स्थान पर मिल सकें।

करनाल सहकारी चीनी मिल ने राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकि दक्षता में प्राप्त किया प्रथम पुरस्कार

राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा 3 जुलाई, 2025 को वर्ष 2023–24 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें करनाल सहकारी चीनी मिल्स को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन उत्कृष्टता के सम्मान में तकनीकी दक्षता (अन्य चीनी प्राप्ति क्षेत्र) में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, भारत सरकार, श्री प्रहलाद जोशी ने की और साथ ही कुछ केंद्रीय एवं राज्य मंत्रियों ने भाग लिया। सहकारिता मंत्री हरियाणा, डॉ. अरविंद कुमार शर्मा और प्रबंध निदेशक, शुगरफेड हरियाणा, कैप्टन शक्ति सिंह, भा.प्र.से, करनाल चीनी मिल्स के अधिकारी, बी.ओ.डी सदस्य और किसान उक्त समारोह में शामिल हुए और पुरस्कार ग्रहण किया।

पिराई सत्र 2023–24 की विशेषताएं–करनाल सहकारी चीनी मिल ने पिराई सत्र 2023–24 दिनांक 15.11.2023 को शुरु किया था और मिल ने दिनांक 11.04.2024 तक 49.34 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करके 04.90 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया था और मिल में पिराई सत्र 2023–24 बिना रुकावट के सफलतापूर्वक सम्पन्न किया था। इस सम्बन्ध में करनाल सहकारी चीनी मिल ने राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकि दक्षता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।यहां पर विशेष तौर पर यह भी उल्लेख किया जाता है कि करनाल सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों की की सुविधा के लिए Online Token System प्रणाली लागू की गई है। जिससे किसान स्वयं अपने गन्ने की ट्रालियों पर टोकन लगा लेते हैं। इसके साथ किसानों की सुविधा के लिए उक्त मिल ने किसानों की सहायता के लिए पिराई सीजन के लिए दो Helpline Number-9034165736, 9034165436 भी दिए हुए हैं। यदि किसानों को कोई समस्या आता है

तो उक्त Helpline Numbers भी पर किसान सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। अब किसान 2 से 3 घंटे में अपनी गन्ने से भरी ट्राली खाली करके वापिस अपने घर चले जाते हैं जिससे मिल में यह प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है। मिल द्वारा अब तक खरीदे गए गन्ने का पूरा भुगतान किसानों को कर दिया है और पिराई सीजन के दौरान भी मिल द्वारा किसानों को 2 से 3 दिनों में गन्ने का भुगतान कर दिया जाता है। इससे किसानों को समय की बचत के साथ–साथ वित्तीय लाभ भी हो रहा है।

इसके अतिरिक्त मिल में स्थापित 18 मेगावाट को0–जन0 प्लांट से 351.38 (लाख) KWH से बिजली का उत्पादन किया था। जिससे मिल को 22.31 करोड़ रूप्ये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ था। पिराई सीजन में करनाल सहकारी चीनी मिल के गन्ना यार्ड में किसानों के लिए रात्रि के ठहराव व चाय के लिए एक विशेष कैन्टीन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, किसानों के भोजन के लिए मिल में अटल मजदूर किसान कैन्टीन भी चलाई जा रही है, जिसमे किसानों की 10 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाता है।

हरियाणा की सभी सहकारी चीनी मिलों को सफलता के नये आयामों पर ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में एवं सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन में कैप्टन शक्ति सिंह, भा.प्र.से, प्रबंध निदेशक, शुगरफैड हरियाणा द्वारा भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम दक्षता अवार्ड मिलने पर सहकारिता विभाग, हरियाणा के लिए गौरवमयी क्षण है। मिल के निदेशक मण्डल के सदस्यों, मिल प्रबन्धकारिणी अधिकारी एवं कर्मचारियों में बडा उत्साह है। इस सन्दर्भ में प्रबन्ध निदेशक महोदय ने किसान भाईओं से यह अपील की है कि इसी तरह साफ–सुथरा गन्ना मिलों मे सप्लाई करते रहें, ताकि मिलें इसी प्रकार से नये आयाम स्थापित करने की ओर अग्रसर रहे और हरियाणा सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार रूप दे सके।

दि हरियाणा राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि. चण्डीगढ़

हरको बैंक द्वारा लोन मेला/सदस्यता अभियान का आयोजन – IYC 2025 पहल के तहत सस्ती ऋण सुविधा पर जोर

हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड (HARCO Bank) द्वारा IYC 2025 (अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष) पहल के अंतर्गत 02 जून, 2025 को सेक्टर–2, पंचकूला में एक विशाल लोन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्देश्य आम जनमानस को सुलभ व किफायती ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना था।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन हरको बैंक के प्रबंध निदेशक डॉ. प्रफुल्ल रंजन द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में उन्होंने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहाः कि "विकास के मार्ग में वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हरको बैंक का उद्देश्य है कि हर वर्ग के व्यक्ति को, सस्ती व पारदर्शी ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं" । मेले में विभिन्न प्रकार के ऋण जैसे व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण, वाहन ऋण, ई–रिक्शा ऋण आदि की जानकारी दी गई एवं ऑन–द–स्पॉट आवेदन की

सुविधा भी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और ऋण संबंधित योजनाओं के प्रति उत्साह दर्शाया। हरको बैंक द्वारा इस तरह के मेले आगे भी राज्यभर में आयोजित किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।

रोहतक वीटा प्लांट के दायरे में 158 नए बूथ स्थान चिन्हित : डॉ. अरविंद शर्मा

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने रोहतक में गोहाना रोड स्थित वीटा मिल्क प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने प्लांट सी.ई.ओ. जयवीर यादव को निर्देश दिए कि वीटा मिल्क प्लांट के दायरे के जिलों से 2 लाख लीटर संकलन के लक्ष्य को लेकर काम करें, ताकि गुणवत्ता से भरपूर वीटा उत्पाद तैयार किए जा सके।

उन्होने बताया कि युवाओं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से प्रदेश में डेयरी फेडरशन द्वारा 10 विभागों में वीटा बूथ स्थापित करने के लिए विशेष कार्य योजना चलाई जा रही है। इसके तहत रोहतक वीटा प्लांट के दायरे में आने वाले 7 जिलों में 158 वीटा बूथ के स्थान चिन्हित किए गए है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इन स्थानों को लेकर जल्द ही प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वीटा उत्पाद घर–घर पहुंचाए जा सकें।

प्लांट की कार्यप्रणाली का लिया जायजा

डॉ. अरविंद शर्मा ने प्लांट को कार्यप्रणाली का जायजा लेने के साथ–साथ रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़ व चरखी दादरी में संचालित हो रहे 155 वीटा बुथों की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि वीटा बुथों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए व डेयरी फैडरेषन के नियमों के अनुसार ही उत्पाद बिक्री सुनिश्चित की जाए। यही नहीं वीटा प्लांट के दूध उत्पादों के अतिरिक्त अन्य कम्पनियों के दूध उत्पाद बेचने वाले वीटा बुथ संचालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वो सहकारी संस्थान के तौर पर वीटा प्लांट के साथ पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि डेयरी फैडरेशन के माध्यम से वीटा उत्पादों को निरन्तर बढ़ावा मिले।

उन्होंने कहा कि वीटा मिल्क प्लांट, रोहतक में देशी घी की जलेबी व समोसे की बेहतर बिक्री हो रही है, इसलिए मानसून के मौसम में घेवर बनाने के भी निर्देश दिए।

शोक समाचार

श्री गजेन्द्र पाराशर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सहकारिता विभाग, हरियाणा (सेवानिवृत) का आकस्मिक निधन

पंचकूलाः– स्वर्गीय श्री गजेन्द्र पाराशर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सहकारिता विभाग हरियाणा (सेवानिवृत) का दिनांक 18 जुलाई 2025 को हद्य गति रूकने से 58 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया है।

सहकारिता विभाग, हरियाणा उनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करता है। एवं प्रभु से प्रार्थना करता है कि भगवान दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस कठिन समय में दुख का सामना करने की शक्ति प्रदान करे।

इन्होनें सन् 1996 में सहकारिता विभाग हरियाणा में सब–ईंस्पेक्टर (ऑडिट) के पद पर ज्वांईन किया और सन् 2025 में वरिष्ठ लेखापरीक्षक के पद से सेवानिवृत हुए। इन्होने अपनी कार्यशैली की सकारात्मक छाप छोड़ी है। उनके निधन से सहकारी क्षेत्र को अपूर्णीय क्षति हुई है। विभाग द्वारा स्वर्गीय श्री गजेन्द्र पाराशर व उनकी कुशल कार्यशैली को सदैव याद किया जायेगा।

वॉकथॉन का आयोजन

क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, सैक्टर–32, चण्डीगढ़ में दिनांक 04.07.2025 का सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की स्थापना के 04 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजेश जोगपाल, आई.ए.एस, पंजीयक, सहकारी समितियाँ, हरियाणा द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया गया।

कार्यक्रम का आरम्भ मुख्य अतिथि द्वारा संस्थान के प्रांगण में भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई पहल 'एक पेड़ माँ के नाम' के अन्तर्गत पौधारोपण करके किया गया। संस्थान द्वारा आयोजित की गई इस वाकॉथान में संस्थान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों, विभागों, बैंको आदि के प्रतिनिधियों एवं संस्थान में संचालित किये जा रहे विभिन्न पाठयक्रमों के लगभग 300 छात्रों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने उत्सापूर्वक भाग लिया गया।

संस्थान द्वारा आयोजित की गई इस वॉकाथॉन का उदेश्य सहकारिता की भावना को जन–जन तक पहुँचाना एवं इसके महत्व को रेखांकित करना था। यह आयोजन संस्थान और सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रयासों का प्रतीक रहा जिसमें सभी सहभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और सहकारिता के संदेश को समाज में फैलाने का संकल्प लिया।

डॉ. राजीव कुमार, निदेशक, क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, चण्डीगढ़ द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथि श्री राजेश जोगपाल, आई.ए.एस. पंजीयक, सहकारी समितयां, हरियाणा एवं कार्यक्रम में भाग लेने वाले संस्थान के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों की सहकारी समितियों, विभागों, बैंको आदि के प्रतिनिधियों एवं संस्थान के छात्रों का धन्यवाद किया गया।

अमूल का खतराज प्लांटः एकीकृत डेयरी वैल्यू चेन का चमकता उदाहरण

1. परिचय

गुजरात के आनंद स्थित अमूल का खतराज प्लांट भारत की दुग्ध क्रांति का प्रकाशस्तंभ है और सहकारी आंदोलन की स्थायी शक्ति का गर्वित प्रतीक भी। 6 जुलाई 2025–यह विशेष तिथि, जब भारत में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की वर्षगांठ मनाई जाती है – को अमूल ने डॉ. वी कुरियन चीज प्लांट में अपनी अत्याधुनिक UHT मिल्क पैकेजिंग लाइन का शुभारंभ किया। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में यह उपलब्धि अमूल की नवाचार, ग्रामीण समृद्धि और सहयोग की भावना के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

2. खतराज प्लांट : एक संक्षिप्त परिचय

उद्घाटन और विस्तार

- 6 जुलाई 2025 को उद्घाटित नई एसेप्टिक UHT मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सुविधा दो अत्याधुनिक लाइनों से सुसज्जित है, जो प्रतिदिन 3 लाख लीटर (LLPD) UHT दूध और अमूल टू जैसे फलों के पेय का प्रसंस्करण कर सकती है।
- यह विस्तार अमूल की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जिससे भारतीय उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतें उच्चतम सुरक्षा, शुद्धता और सुविधा के साथ पूरी हो रही हैं।

चीज़ और पनीर उत्पादन

- खतराज प्लांट भारत का सबसे बड़ा चीज निर्माण केंद्र है, जहां प्रतिदिन लगभग 50 मीट्रिक टन चीज़, देश का पहला पूर्ण स्वचालित पनीर संयंत्र और आधुनिक व्हे ड्राइंग यूनिट स्थापित है।
- प्रोसेस्ड चीज ब्लॉक्स और चिपलेट्स के लिए हाई–स्पीड पैकिंग लाइन और 6,200 पैलेट्स की क्षमता वाला इलेक्ट्रिक स्मार्ट शटल सिस्टम युक्त ऑटोमेटेड वेयरहाउस इसकी विश्वस्तरीय दक्षता को दर्शाता है।

संसाधनों की दक्षता

- अमूल की संसाधन अनुकूलन के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट है – चीज और पनीर निर्माण से निकलने वाले व्हे का उपयोग लस्सी, छाछ और व्हे प्रोटीन कंसंट्रेट (WPC 80) जैसे उच्च प्रोटीन उत्पादों में किया जाता है।
- इससे न केवल अपशिष्ट कम होता है, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला, किफायती प्रोटीन भी मिलता है. जिससे देश की प्रोटीन खाई पाटने और स्वस्थ भारत के निर्माण में मदद मिलती है।

3. तकनीकी नवाचार

UHT मिल्क पैकेजिंग

- नवीनतम UHT स्टेरिलाइजर्स और एसेप्टिक फिलिंग लाइनों का उपयोग दूध की शेल्फ लाइफ को बिना प्रिजर्वेटिव के बढ़ाता है. जिससे भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक भी सुरक्षित और सुविधाजनक दूध पहुंचाना संभव होता है।
- यह तकनीक सुनिश्चित करती है कि हर भारतीय परिवार को ताजा, पौष्टिक दूध मिले – चाहे वे देश के किसी भी कोने में हों।

निर्यात के लिए मोजरेला चीज

- संयंत्र की नई, पूर्ण स्वचालित 20 डज्क्व मोजरेला चीज लाइन, उन्नत वेट्स, इनलाइन मैच्युरेशन टनल्स, स्ट्रेचिंग और मोल्डिंग मशीनों, प्फथ तकनीक और आधुनिक पैकेजिंग से लैस है।
- यहां बना बफेलो मोजरेला चीज 50 से अधिक देशों में निर्यात होता है. ''मेड इन इंडिया'' का गौरव विश्वभर में फैलाता है और अमूल की वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करता है।

एकीकृत वैल्यू एडिशन

- संयंत्र में 5 MTPD योगर्ट निर्माण इकाई और 5 MTPD श्रीखंड प्लांट भी है, जिसमें अल्ट्रा–क्लीन टैंक, स्टेराइल एयर सिस्टम और एसेप्टिक फ्रूट डोजिंग सिस्टम लगे हैं।
- ये सुविधाएं अमूल को प्रीमियम योगर्ट और श्रीखंड की रेंज पेश करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को और अधिक मूल्य मिलता है।

4. सामाजिक–आर्थिक लाभ

किसानों को सशक्त बनाना

- अमूल द्वारा नर्मदा शुगर कोऑपरेटिव से चीनी और अन्य सहकारी समितियों से फलों का गूदा खरीदने से न केवल दुग्ध उत्पादक, बल्कि गन्ना और फल उत्पादक किसानों की भी समृद्धि सुनिश्चित होती है।
- यह आपसी सहयोग का मॉडल पूरे ग्रामीण समाज को सशक्त करता है और साझा समृद्धि को बढ़ावा देता है।

रोजगार सृजन

- विस्तार से अनेक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बने हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और सहायक क्षेत्रों को समर्थन मिला है।
- संयंत्र संचालन से लेकर लॉजिस्टिक्स और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हजारों लोग अमूल की वृद्धि से लाभान्वित हो रहे हैं।

उत्पादकों के लिए मूल्य

- हर स्तर पर मूल्य संवर्धन से दुग्ध उत्पादकों को अधिक लाभ मिलता है, जिससे सहकारी मॉडल की सफलता और मजबूत होती है।
- अमूल के निवेश किसानों को उनके दूध का बेहतर मूल्य दिलाते हैं और समृद्धि का चक्र रचते हैं।

5. निर्यात और बाजार के अवसर

वैश्विक पहुंच

- अमूल के विश्वस्तरीय उत्पाद, विशेषकर बफेलो मोज़रेला चीज, 50 से अधिक देशों में पहुंचते हैं, जिससे भारतीय डेयरी की वैश्विक प्रतिष्ठा और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
- यह वैश्विक उपस्थिति भारतीय डेयरी के लिए नए मानक स्थापित करती है।

घरेलू मांग की पूर्ति

- सुरक्षित, सुविधाजनक और पौष्टिक डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ, खतराज प्लांट भारतीय बाजार की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
- पैकेजिंग और वितरण में नवाचार से अमूल के उत्पाद देश के हर कोने तक पहुंचते हैं।

6. सततता और संसाधन प्रबंधन

उप–उत्पादों का कुशल उपयोग

- व्हे को उच्च प्रोटीन पेय में बदलना संसाधन दक्षता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- यह टिकाऊ दृष्टिकोण कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करता है और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देता है।

आधुनिक अवसंरचना

- ऑटोमेटेड वेयरहाउस, हाई–स्पीड पैकिंग लाइन और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स सिस्टम न्यूनतम अपशिष्ट और संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।
- ये नवाचार अमूल को संचालन की उत्कृष्टता में अग्रणी बनाए रखते हैं।

7. राष्ट्रीय महत्व का दिन

- 6 जुलाई को उद्घाटन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की वर्षगांठ भी है एक ऐसा मंत्रालय जो भारत के सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है।
- यह संयोग अमूल की भूमिका को रेखांकित करता है, जो सहकारी भावना का अग्रदूत बनकर ग्रामीण भारत में प्रगति और एकता का संचार कर रहा है।

8. निष्कर्ष

अमूल का खतराज प्लांट केवल एक डेयरी संयंत्र नहीं, बल्कि नवाचार, सहयोग और ग्रामीण सशक्तिकरण का प्रतीक है। अत्याधुनिक तकनीक को सहकारी भावना से जोड़कर अमूल भारतीय डेयरी क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। किसानों, उपभोक्ताओं और राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ, अमूल एक स्वस्थ, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है–अपने आदर्ष वाक्य ''अमूलःदे टेस्ट ऑफ इंडिया'' को साकार करते हुए।

Dr. Diksha Sharma
Lecturer, Regional Institute of Cooperative Management,
Sector 32 C, Chandigarh

हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि0

बेज नं0 49–52, सेक्टर–02, पंचकुला

दूरभाष नं0: 0172–2560340, 0172–2560332
ई–मेलः– harcofed@ymail.com
वेबसाइटः– https://www.harcofed.org.in

क्रमांक/शि.शा./सा.नि.–2025/ 3632-4481 दिनांकः 23-07-2025

प्रेषित,

सभी सदस्य,
हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि0, पंचकूला।
हरियाणा राज्य में। (संबंधित ACEO/EI के माध्यम से)

विषयः– **हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि0 की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक हेतु प्रतिनिधियों के नामांकन बारे ।**

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि0 (हरकोफैड) की सामान्य निकाय की वार्षिक बैठक का आयोजन **दिनांक 11.08.2025 दिन सोमवार को दोपहर 11.30 बजे Red Bishop, सेक्टर–01 पंचकूला** में होनी निश्चित हुई है। जिसमें सदस्य संस्था/समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा मनोनीत एक ही प्रतिनिधि भाग लेगा।

बैठक की कार्यसूची मदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. **हरकोफैड की दिनांक 30.07.2024 को हुई सामान्य निकाय की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि करने बारे।**
2. **हरकोफैड की वर्ष 2024–25 में वार्षिक कार्य–योजना अनुसार की गई प्रगति पर विचार करने बारे।**
3. **हरकोफैड की वर्ष 2024–25 की आडिटिड तुलन–पत्र (Balance-sheet) पर विचार बारे।**
4. **हरकोफैड के निदेशक मण्डल द्वारा जारी वर्ष 2025–26 की वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन हेतु।**

अतः अनुरोध है कि संबंधित संस्था/समिति सक्षम निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव की एक सत्यापित प्रति तथा नामांकन–पत्र दिनांक 05.08.2025 तक हरकोफैड मुख्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

आप सभी से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा रखते हुए।

प्रबन्ध निदेशक

संलग्नः–नामांकन फॉर्म।

क्रमांक/शि.शा./सा.नि.–2025/ दिनांकः

उपरोक्त की प्रति सभी सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारियों व सभी शिक्षा अनुदेशकों को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने क्षेत्र में सदस्य समितियों/संस्थाओं को सलंग्न सदस्य समितियों/संस्थाओं की सूची अनुसार मुख्यालय के पत्र व समिति/संस्था के सदस्य के नामांकन फॉर्म की प्रति भिजवाकर पावति मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

—sd—
प्रबन्ध निदेशक

'अनुलग्नक–क'

हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि0 (हरकोफैड) की वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली वार्षिक आम सभा की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि का नामांकन–पत्रः–

1– सदस्य समिति/संस्था का नामः–.....

2– संस्था का पताः– .....

3– प्रतिनिधि बारे विवरणः– .....

सदस्य का नाम एवं पद	प्रतिनिधि का पत्र व्यवहार का पता व दूरभाष नं0	प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
		हस्ताक्षर सत्यापित (संस्था के इन्चार्ज/निरीक्षक/शिक्षा अनुदेशक या ए.सी.ई.ओ.द्वारा

4. प्रतिनिधि संस्था/समिति की प्रस्ताव संख्या ..... दिनांक ..... को सम्पन्न..... (प्रबन्ध कमेटी/निदेशक मण्डल/प्रशासक मण्डल) द्वारा मनोनीत किया गया।

5. प्रस्ताव करने वाली प्रबन्ध कमेटी/निदेशक मण्डल/प्रशासक मण्डल के कार्यकाल समाप्ति की तिथि .....

संस्था की मोहर

हस्ताक्षर
(संस्था के अधिकारी)

नोटः– पारित प्रस्ताव की सत्यापित प्रति फार्म के साथ संलग्न करें।

The Haryana State Cooperative Development Federation Ltd.,
Bays 49-52 Sector-2, Panchkula
Phone:-0172-2560340, Fax:-0172-2560332
Email:harcofed@ymail.com

सूचना

विषयः हरियाणा राज्य की सहकारी समितियां के लिए हरकोफैड की सदस्यता लेने के लिए आवेदन संबंधी सूचना।

यह सूचित किया जाता है कि जो भी सहकारी समिति हरियाणा राज्य में हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि.(हरकोफैड) की सदस्यता लेना चाहती है, वह संस्था द्वारा निर्धारित नियमों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकती है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.07.2025 है।

सदस्यता के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैः–

1. सदस्यता हेतु प्रार्थना पत्र।
2. समिति का नाम, पूरा पता, पीन कोड, ई–मेल आई.डी., फोन नं0।
3. समिति की पंजीकरण प्रमाण पत्र।
4. समिति के उप–नियम।
5. समिति के पिछले तीन वर्षो की आडिट रिपोर्ट या लेखा विवरण।
6. समिति के प्रमुख पदाधिकारियों की सूची जिसमें उनका नाम, पद, पता, मो0न0, ई0मेल0 आई.डी. वर्णित हो।
7. सहकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव जोकि संबंधित सहायक रजिस्ट्रार/निरीक्षक सहकारी समितियां से सत्यापित हो।
8. सहकारी समिति बचत खाता नं0, बैंक का नाम व पता ।
9. सहकारी समिति का जी.एस.टी. नं0/पैन नं0 इत्यादि।
10. सहकारी समिति के सचिव/प्रधान/प्रबंधक का नाम, पता, मो0 नं0, ई–मेल आई.डी.।
11. प्रमाण पत्र जिसमें सहकारी समिति के सचिव/प्रधान/प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया गया हो की सहकारी समिति संस्था के नियमों के अनुसार वांछनीय योग्यता पूर्ण करती है तथा संलग्न दस्तावेज व तथ्य पूर्ण जांच उपरांत भेजे गए हैं और सभी दस्तावेज सही सही हैं। यह सहकारी समिति परिसमापनाधीन नहीं है और वार्षिक बैलंस सीट अनुसार समिति डिफन्कट/निष्क्रिय नहीं है, चालू हालत में है।
12. आपके प्रार्थना पत्र पर नियमों के मध्यनजर अंतिम फैसला निदेशक मंडल द्वारा लिया जाएगा। सदस्यता के संबंद में निदेशक मंडल द्वारा निर्णय लेने उपरांत ही आप द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी विकास प्रसंघ लि.(हरकोफैड) के तत्काल उप नियमों में वर्णित सदस्यता हेतु जरूरी दाखिला फीस व शेयर पूंजी जमा करवानी होगी।
13. उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था पर वर्तमान में लागू व समयानुसर परवर्तित नियमों/उप नियमों को ध्यान में रखते हुए हर तरह से पूर्ण अपना आवेदन संस्था की सदस्यता ग्रहण करने हेतु अपना आवदेन संस्था को भेज सकते हैं।

इच्छुक समितियां अपना आवेदन पत्र पूर्ण तथ्यों व दस्तावेजों सहित हमारी संस्था के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भिजवा सकती हैं।

दिनांकः 18.07.2025.
स्थानः पंचकुला।

प्रबंध निदेशक

हरकोफैड/2025/3531-81 दिनांक 18/07/25

1. उपरोक्त की प्रति माननीय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय, सभी उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां व सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां हरियाणा राज्य में को अपने नोटिस बोर्ड पर सूचनार्थ प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित है।
2. सभी सहायक सहकारी शिक्षा अधिकारी व शिक्षा अनुदेशक, हरकोफैड को निर्देश दिए जाते हैं की सहकारी समितियों से जो आवेदन प्राप्त होते हैं उनकी पूर्ण जांच उपरांत ही मुख्यालय को भिजवाएं।
3. प्रोग्रामर कार्यालय हरकोफैड, पंचकुला को संस्था की Website पर Upload करने बारे।

प्रबन्ध निदेशक

लघुकथाः

धागा

पिछले रक्षाबंधन के उपरांत पूरे एक साल तक मैं जिन हालात से गुजरा था सभी जानते हैं। करुणा भी मेरे हालात से अनजान नहीं थी। मदद तो दूर साल भर तक उसने न तो कभी हमारे घर आने की जरूरत समझी और न ही कुछ पूछताछ करने की। क्या साल में एक दिन भाई की कलाई पर एक धागा लपेट देने मात्र से भाई–बहन के इस पवित्र और महत्त्वपूर्ण रिश्ते को सँभालकर रखा जा सकता है? मैंने फैसला कर लिया कि करुणा और उसके परिवार के सदस्यों से कोई संबंध नहीं रखूँगा। बेशक करुणा मेरी इकलौती बहन है और मैं उसका इकलौता भाई लेकिन दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये निर्णय ले लिया कि भविष्य में कभी भी उससे राखी नहीं बँधवाऊँगा। ''जब दिलों में ही प्रेम नहीं तो प्रेम का नाटक करने का क्या औचित्य हो सकता है?'' किसी भी तरह ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने अपने निर्णय से घर के सभी सदस्यों को अवगत करा दिया था। अगले रक्षाबंधन पर अलबत्ता तो करुणा आएगी ही नहीं और अगर आएगी भी तो मैं किसी भी कीमत पर उससे राखी नहीं बँधवाऊँगा।

रक्षाबंधन निकट ही था। घर में बेचैनी व्याप्त हो गई। माँ, पत्नी और बच्चे सभी मेरे इस निर्णय से बेहद दुखी नजर आ रहे थे। आखिर रक्षाबंधन का दिन भी आ ही पहुँचा। वैसे तो करुणा प्रायः दोपहर के बाद ही आती थी लेकिन आज वो सुबह–सुबह ही आ पहुँची। हम चाय पी रहे थे। चाय–नाश्ता छोड़कर बच्चे अपनी बुआ से लिपट गए। उनकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थीं। करुणा ने बच्चों से कहा कि तुमसे बाद में निपटूँगी पहले मुझे अपने भाई प्रदीप को राखी बाँधने दो। वह किचन में गई और वहाँ से थाली लेकर उसमें राखी, मिठाइयाँ व अन्य जरूरी चीजें रखकर सीधे मेरे पास पहुँची। जैसे ही उसने थाली मेज पर रखकर राखी उठाई मैंने चुपचाप अपनी कलाई उसकी तरफ बढ़ा दी। मेरा पाषाण–हृदय मेरा साथ छोड़ चुका था। करुणा और उसके परिवार के सभी सदस्यों के लिए आशीर्वादों की वर्षा हो रही थी। पवित्र भावों से निर्मित एक सूक्ष्म–सा धागा रिश्तों को बखूबी सँभालने में सक्षम था।

सीताराम गुप्ता,
ए.डी. 106 सी., पीतमपुरा, दिल्ली – 110034, मोबा0 नं0 9555622323, Email - srgupta54@yahoo-co-in

पौधे की व्यथा

मैं एक पौधा हूं,
बस, इस इंतजार में,
बरसात का मौसम है,
कोई मुझे भी चिकलाएगा,
किसी सार्वजनिक जगह पर,
एक भला मानस, मुझे ले जाएगा,
चारों ओर ढोल बजाकर बताएगा,
पौधारोपण समारोह में आइए,
वन महोत्सव है, पेड़ लगाईए,
गड्ढ़ा भी खुदेगा, सफेदी भी पड़ेगी,
फोटोग्राफर भी होगा, ताली बजेगी,
मुझे मेरे जन्म स्थान से निकालकर,
खुशियों के बीच, मैं खड़ा होकर सोचूंगा,
क्या ये मिट्टी, ये खाद, ये पानी, ये मान,
मेरी मौत से पहले, मेरी अंतिम इच्छा है,
क्योंकि,
मात्र औपचारिकता के बाद,
कोई भी बहरूपिया मुझे अगले साल तक,
क्या देखेंगा भी, आएगा भी, पूछेगा भी, संभालेगा भी
यदि नही तो फिर यह आडम्बर क्यों,
क्यूं मुझे मेरे जन्म स्थान से महरूम किया,
क्यूं मुझे हर साल
क्यूं उसी जगह, उसी मौसम में, उन्हीं लोगों द्वारा,
पौधारोपण की आड़ में, पुनः गड्ढ़ा खोदकर
मां धरती में समाए मेरे अस्थी पिंजर को कुरेदा जाता है।
इतिहास गवाह है कि हर पौधा
अपने जन्म स्थल पर, मां धरती की गोद में
बड़ा हुआ, वृक्ष बना है, जंगल बना है,
संरक्षक बना है, पालक बना है,
प्रकृति बना है, सुंदरता बना है,
हर जीव जंतु पशु पक्षी का पोषक बना है
परन्तु
अपने स्वार्थ में, मेरी महिमा मंडन करने वालों ने
सदैव मुझे छला है, छला है, छला है .....

लेखक :
श्रीनारायण कौशिक
शिक्षा अनुदेशक, हरकोफैड

डेयरी क्षेत्र का विकास : श्वेत क्रांति 2.0

वर्तमान में दूध उत्पादन 239 मिलियन टन तक पहुँचने के साथ भारत अकेले वैश्विक उत्पादन में एक चौथाई योगदान देता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 2023–24 के लिए 471 ग्राम प्रतिदिन है जो कि खाद्य आउटलुक जून 2023 में बताई गई वैश्विक औसत 322 ग्राम प्रतिदिन से से काफी अधिक है। डेयरी क्षेत्र को 22 दूध संघों/शीर्ष निकायों, 240 जिला सहकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें लगभग 2,30,000 गाँव और 18 मिलियन डेयरी किसान सदस्य हैं। वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत 24,000 से अधिक कृशक उत्पादक संगठन पंजीकृत हैं, जो कई कृशि गतिविधियाँ करते हैं, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 2027–28 तक 10,000 और कृशक उत्पादक संगठनों का पोशण किया जना है।

आज देश में उत्पादित कुल दूध का 12 प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा खरीदा जाता है, 12 प्रतिशत निजी क्षेत्र द्वारा, 37 प्रतिशत दूध किसानों द्वारा स्वयं उपभोग के लिए रखा जाता है और शेश 39 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र द्वारा खरीदा और प्रबंधित किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी का योगदान करीब 5 प्रतिशत है। पिछले 10 वर्शों में दूध उत्पादन में करीब 63–56 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आज देश में उत्पादित दूध का मूल्य 11.16 लाख करोड़ रूपये है जो इसे मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ा कृशि उत्पाद बनाता है। यहाँ तक कि अनाज दालों और गन्ने के संयुक्त मूल्य को भी पार कर जाता है।

आज लगभग 8 करोड़ ग्रामीण परिवार दूध उत्पादन में लगे हुए हैं जिनमें से 85 प्रतिशत भूमिहीन लोग, छोटे और सीमांत किसान हैं। भारत में डेयरी सहकारी समितियाँ उपभोक्ता व्यय का औसतन 75.80 प्रतिशत डेयरी सहकारी समितियों ने मिलकर लगभग 95,000 करोड़ रूपये का भुगतान किया जो प्रत्येक दिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगभग 260 करोड़ रूपये डालने के बराबर है जो किसी भी अन्य क्षेत्र द्वारा बेजोड़ उपलब्धि है।

15वें वित्त आयोग चक्र (2021–22 से 2025–26) के लिए 2,790 करोड़ रूपये के बढ़ते हुए बजट के साथ इस पहल का उद्देश्य डेयरी बुनियादी ढ़ांचे का आधुनिकीकरण करना, दूध खरीद और प्रसंस्करण क्षमताओं को मजबूत करना और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करना है। विशेश रूप से कार्यक्रम 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना और पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में दो दूध उत्पादक कंपनियों के गठन पर जोर देता है। अनुमानित 3,20,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं को लाभान्वित करना है जो डेयरी कार्यबल का 70 प्रतिशत हिस्सा है।

श्वते क्रान्ति 2.0 :– 1970 के दशक के पूर्वार्ध में शुरू की गयी श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड में डॉ. वर्गीज कुरिजन के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय डेयरी उद्योग की गौरवशाली यात्रा की शुरूआत हुई जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया और करोड़ों छोट–डेयरी किसानों की आजीविका में सार्थक सुधार किया।

प्रथम श्वेत क्रांति की बुनियादी सहकारिताओं के विकास और दूध उत्पादन में वृद्धि के आधार पर रखी गई थी। जबकि श्वेत क्रांति 2.0 का ताना बाना नए जमाने की आावश्यकताओं और उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के गिर्द बुना जा रहा है। जैसे आधुनिक प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन की चुनौती और विभिन्न डेयरी उत्पादों की तेजी से बढ़ती बाजार मांग आदि। श्वेत क्रांति 2.0 के अभियान को राज्य सरकारों, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट फंड द्वारा समर्थन और सहायता प्रदान की जा रही है तथा दूसरे चरण में पशु उत्पाकता में ठहराव, उपभोक्ताओं की बदलती प्राथमिकताओं और विकास जैसी नई चुनौतियों के समाधान पर भी ध्यान जा रहा है।

- सहकारिता के माध्यम से संचालित श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य सहकारी कवरेज में विस्तार, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण है और इसका उद्देश्य अगले पाँच वर्शों में अनाच्छादित क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों को बाजार की पहुँच उपलब्ध कराकर और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारिताओं की हिस्सेदारी को बढ़ाकर डेयरी सहकारिताओं द्वारा दूध संकलन को वर्तमान स्तर से 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है।
- श्वेत क्रांति 2.0 के अंतर्गत परिकल्पित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहकारी दूध संकलन में वर्तमान 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के मुकाबले प्रतिवर्श लगभग 9 प्रतिशत की वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- पांचवे वर्ष के अंत तक डेयरी सहकारिताओं द्वारा दूध का संकलन बढ़कर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन होने की

रेखा दहिया और मोनिका वर्मा

पशु विज्ञान केन्द्र, पलवल, पशुजन्य उत्पाद प्रौद्योगिका विभाग
लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार

संभावना है जोकि वर्तमान में 660 लाख किलोग्राम प्रतिदिन है।

- अगले पांच वर्शों के दौरान लगभग 56,000 नए बहु उद्देशीय डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है। नई बहु उद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों/बहु उद्देशीय प्राथमिक कृशि सहकारी ऋण समितियों का निर्माण करने की बजाय यथा संभवतः बहु उद्देशीय प्राथमिक कृशि सहकारी ऋण समितियों में दूध संकलन गतिविधियों की शुरूआत करके अनाच्छादित क्षेत्रों में मौजूदा प्राथमिक कृशि सहकारी ऋण समितियों के लाभ लेने के प्रयास किए जाएंगे।
- बेहतर और उन्नत दूध संकलन तथा परीक्षण के बुनियादी ढ़ांचों जैसे स्वचालित दूध संकलन इकाई, डेटा प्रोसेसर दूध संकलन इकाई, परीक्षण उपकरण, बल्क मिल्क कूलर आदि को आवश्यकतानुसार लगाकर लगभग 46,000 वर्तमान ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों/प्राथमिक कृशि सहकारी ऋण समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और वे बहु उद्देशीय डेयरी सहकारी समितियों/बहु उद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के रूप में कार्य करेंगे।

बहु उद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में डेयरी की गतिविधियों की शुरूआत करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के संसाधनों से 40,000 रूपये प्रति बहु उद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों की दर से 1,000 बहु उद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदार कर श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया जा रहा है। तदुपरांत, इस पहलू को पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के प्रस्तावित राश्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0 की वित्तीय सहायता से आगे बढ़ाया जाएगा। इस पहल से सहकारिता आन्दोलन और मजबूत बनकर उभरेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी देना भारत के कृशि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0

- **घटक ए :** आवश्यक डेयरी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए समर्पित है जैसे कि दूध ठंडा करने वाले संयंत्र, उन्नत दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्रमाणन प्रणाली। यह नई ग्राम डेयरी सहकारी समितियों के गठन का भी समर्थन करता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूध खरीद ओर पिछड़े क्षेत्रों में साथ ही समर्पित करता है, विशेश रूप से दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में साथ ही समर्पित अनुदान सहायता के साथ–साथ दूध उत्पादक कंपनियों का गठन करता है।
- **घटक बी :** जिसे सहकारिता के माध्यम से डेयरी के रूप में जाना जाता है। हस्ताक्षरित समझौतों के अनुसार जापान सरकार और जापान अंतर्राश्ट्रीय सहयोग एजेंसी के साथ सहयोग के माध्यम से डेयरी विकास को बढ़ावा देना जारी रखेगा। यह घटक नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में डेयरी सहकारी समितियों के सतत विकास उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन बुनियादी ढांचे में सुधा पर केंद्रित है। राश्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन ने पहले से ही 18.74 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित करते हुए बहुत बड़ा सामाजिक–आर्थिक प्रभाव डाला है और 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं और अतिरिक्त 100.95 लाख लीटर प्रति दिन दूध खरीद क्षमता में वृद्धि की है। 51,777 से अधिक ग्राम–स्तरीय दूध परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत किया गया है। जबकि 123.33 लाख लीटर की संयुक्त क्षमता वाले 5,123 बल्क मिल्क कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा 169 प्रयोगशालाओं को फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड दूध विश्लेशक के साथ अपग्रेड किया गया है। संशोधित राश्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना और प्रसंस्करण के साथ–साथ गठन करने की भी उम्मीद है।

ऑपरेशन फ्लड के बाद कई बड़े पैमाने पर डेयरी विकास कार्यक्रम जैसे राश्ट्रीय डेयरी योजना–1, राश्ट्रीय गोकुल मिशन, राश्ट्रीय पशुधन मिशन, राश्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन, राश्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम आदि जैसे कई बड़े पैमाने के कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखा है।

पिछले 7 दशकों में डेयरी सहकारी समितियों ने एक व्यापक डेयरी मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। इस श्रंखला में गाँवों में उत्पादकों से करोड़ों लीटर दूध इकट्ठा करना उसका प्रसंस्करण करना उसे विभिन्न प्रकार के पौश्टिक डेयरी उत्पादों में बदलना और साल के हर दिन लगातार 6,000 से अधिक शहरों में उपभोक्ताओं तक पहुँचाना शामिल है।

विश्व डेयरी बाजार में हमारी हिस्सेदारी फिलहाल एक प्रतिशत से भी कम हैं। डेयरी निर्यात में वृद्धि इस क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूण्र है। भारत को गैर–टैरिफ बाधाओं अप्रतिस्पर्धा कीमतों और प्रभावी विपणन सहित मुदों को संबोधित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को कम करने के लिए कई हिस्सेदारी को लगभग 10 प्रतिशत तक बढ़ाना है।

डेयरी विजन 2047 का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाने, संगठित क्षेत्र का विस्तार और वैश्विक बाजार में भारतीय डेयरी उत्पादों की पैठ बनाने पर जो दिया जाएगा। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ेगे हमें यह याद रखना होगा कि डेयरी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ओर उसे विकसित भारत 2047 की सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।

भारत सरकार की डेयरी किसान हितैशी योजनाओं के प्रति डेयरी किसानों में जागरूकता के प्रसार की आवश्यकता है। युवाओं को डेयरी क्षेत्र से होने वाली आकर्शक आमदनी के प्रति जागयकता जगानी होगी क्योंकि युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में रूचि नहीं दिखा रही है। 'सहकार–से–समृद्धि' के सपने को साकार करने के लिए तथा देश में सहकारिताएं बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में समृद्धि और आत्मनिर्भरता आएगी।

हरकोफैड द्वारा पूरे हरियाणा में किया गया एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण कार्यक्रम लगाए 1100 पौधे

SAHKAR SE SAMRIDDHI
Aatmanirabhar Bharat, Aatmanirbhar Krishi

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

IFFCO NANO UREA Plus
and
IFFCO NANO DAP
Promises
More Yield And More Profit

World's First Nano Fertilizer by IFFCO

500 ML Bottle ₹225/- only
Contains 20% NITROGEN
FREE ACCIDENT INSURANCE
IFFCO Nano UREA Plus Liquid

500 ML Bottle ₹600/- only
IFFCO Nano DAP Liquid

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED
IFFCO Sadan, C-1 District Centre, Saket Place, New Delhi - 110017, INDIA
Phones: 91-11-26510001, 91-11-42592626. Website: www.iffco.coop

हरियाणा के नवनियुक्त महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर अशीम कुमार घोष एवं उनकी धर्मपत्नी जी को राजभवन हरियाणा, चण्डीगढ़ में पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी।

हरकोफैड के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता करते श्री कुलदीप, निदेशक। बैठक में हिस्सा लेते निदेशक हरकोफैड के सभी निदेशक, प्रबंध निदेशक हरकोफैड श्री नरेश गोयल, संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां श्री योगेश शर्मा।

हरियाणा राज्य सहकारी विकास फैडरेशन की ओर से सौरव शर्मा संपादक द्वारा हरियाणा सहकारी प्रैस 165–166, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, चण्डीगढ़ से मुद्रित व प्रकाशित तथा कार्यालय बेज नं. 49–52, प्रथम तल, सेक्टर–2, पंचकूला ।
दूरभाष : 0172–2560340, 2560332 हरकोप्रैस : 0172–2637264